



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 27 जुलाई, 1996/5 श्रावण, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्थानीय स्वशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 जुलाई, 1996

संख्या एल०एस०जी०-बी (2) 2/89.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश शहरी स्थानीय निकाए निदेशालय में विभिन्न सहायक वर्ग-III (अराजपत्रित) पद के इस अधिसूचना के संलग्न उपाबन्ध “अ” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश शहरी स्थानीय निकाए निदेशालय विभाग विधि सहायक वर्ग-III (अराजपत्रित) पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,  
पी 0 एस 0 राणा,  
वित्तायुक्त एवं सचिव।

उद्भाव्य "अ"

शहरी स्वामीय निकाय विभाग, हिमाचल प्रदेश में विधि सहायक (अराजपत्रित) श्रेणी-III के पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम

1. पद का नाम	विधि सहायक
2. पदों का संख्या	1 (एक)
3. वर्गीकरण	वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिकीय सेवायें
4. वेतनमान	रु 18 00-50-2000-60-2060-70-2550-75-3000-100-3200.
5. चयन	अचयन
6. संघी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु।	18 से 35 वर्ष :

परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गए पहले से सरकार की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख की अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के

प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेसन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जायेगी जैसी सरकारी कर्मचारियों की अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिकृत्त को नहीं दी जायेगी जो पश्चात्पूर्ति ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किये गये थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेसित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उम्र वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें यथा स्थिति पद विज्ञापित या नियोजनालयों को अधिसूचित किये जाते हैं।

(2) अन्यथा सुप्रसिद्ध अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं।

(क) अनिवार्य :

भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम विधि स्नातक की व्यवसायिक उपाधि या इसके समकक्ष सहित तीन वर्ष का विधि व्यवसाय का अनुभव या सरकारी/अर्धसरकारी संस्थानों में कार्य का पांच वर्ष का अनुभव रखता हो।

(ख) वांछनीय अर्हताएं:

हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयोगिता

8. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।

आयु : लागू नहीं  
शैक्षणिक अर्हताएं : लागू

9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति--भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण

शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा, और दोनों के न होने

द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।

पर सीधी भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा।

उपर्युक्त स्तम्भ 7 में विहित शैक्षणिक अर्हता के अधीन शैक्षणिक अर्हताएं पूर्ण करता हो, लिपिक क/डर (लिपिक/वरिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ सहायकों को, सम्मिलित करके) में पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या 31-3-91 तक की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित कर पांच वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, में से प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में समतुल्य वेतनमान में कार्यरत विधि सहायकों के पद के पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए सभी पात्र पदधारियों की एक चयनित सूची तैयार की जायेगी जिसमें उच्च वेतनमानों वाले अभ्यर्थियों को सामुहिक रूप में अन्य पात्र व्यक्तियों से उपर रखा जाएगा और उसके पश्चात अगले निम्न वेतनमान वाले अभ्यर्थियों को इसी प्रकार इत के नीचे रखा जाएगा।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व संभरण पद में 31-3-91 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिए इन शर्तों के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी।

(i) उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति संभरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-1991 तक की गई तदर्थ सेवा को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, कम से कम 3 वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पदवांसी परन्तु की प्रपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के निम्ने प्रभाव हो जाता है, वहां उपर

कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा।

**स्पष्टीकरण.**—अन्तिम परन्तु के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक हो, जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्स परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रूज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अनुसार भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हो या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित व्यक्ति से पूर्व 31-3-1991 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी :

परन्तु 31-3-1991 तक तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेंगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना।

भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

संधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रपेक्षा।

जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो

कितनी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का निम्नलिखित होना आवश्यक है :—

- (क) भारत का नागरिक, या
- (ख) नेपाल की प्रजा, या
- (ग) भूटान की प्रजा, या
- (घ) तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थाई निवास के आशय से आया हो, या
- (ङ) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जिसने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका के देशों या कीनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पहले तांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मालावी, जेयरे और इथोपिया से भारत में स्थाई निवास के आशय से प्रवास किया है :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

ऐसे अभ्यर्थी को, जिनके मामले में पत्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा/साक्षात्कार में प्रविष्ट किया जा सकेगा, किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उसे पात्रता का अपेक्षित प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के पश्चात् ही दिया जाएगा।

15. मौखी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।

सौख्य भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर, और यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

16. आरक्षण

उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों और अथ प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गये अनुदेशों के अधीन होगी।

17. शिथिल करने की शक्ति

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

[Authoritative English text of this Government notification No. LSG. B (2) 2/89, dated 6th July, 1996, as required under clause (3) of Article 343 of the Constitution of India].

## LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th July, 1996

No. LSG. B (2) 2/89.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Legal Assistant (Class-III) (Non-Gazetted) in Directorate of Urban Local Bodies, Himachal Pradesh as per Annexure 'A' appended to this notification, namely :—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called Directorate of Urban Local Bodies, Himachal Pradesh Legal Assistant (Class-III) (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1996.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,  
P. S. RANA,  
Financial Commissioner-cum-Secretary.  
ANNEXURE 'A'

**RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF LEGAL ASSISTANT  
CLASS-III (NON-GAZETTED) IN THE DIRECTORATE OF URBAN LOCAL BODIES,  
HIMACHAL PRADESH**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Name of the post                              | Legal Assistant                                    |
| 2. Number of posts                               | 1 (One).   |
| 3. Classification                                | Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services.     |
| 4. Scale of pay                                  | Rs. 1800-50-2000-60-2060-70-2550-75-3000-100-3200. |
| 5. Whether selection post or non-selection post. | Non-selection.                                     |
| 6. Age for direct recruitment                    | Between 18 and 35 years :                          |

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis or on contract basis had become overage on the date when he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such *ad hoc* or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Govt. servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age

concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.

*(a) Essential qualifications :*

Should possess a professional degree in Law or its equivalent from any recognised University in India with 3 years experience as a practising Advocate or 5 years experience while working in a Government/Semi Government Institutions.

*(b) Desirable qualifications :*

Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

*Age :* Not applicable.

*Educational qualifications :* Yes.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.

9. Period of probation, if any

Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.

100% by promotion, failing which by deputation/transfer and failing both by direct recruitment.



persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation *ad hoc* service rendered on the feeder post upto 31-3-91, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service:

Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account *ad hoc* service rendered upto 31-3-1991 shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?

As may be constituted by the Govt. from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.

A candidate for appointment to any service or post must be :—

- (a) a citizen of India, or
- (b) a subject of Nepal, or
- (c) a subject of Bhutan, or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India,
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) Zambia, Malwa, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

**15. Selection for appointment to post by direct recruitment.**

Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva voce* test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or a practical test, the standard/syllabus, etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority as the case may be.

**16. Reservation**

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

**17. Powers to Relax**

Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

